

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 2430-तीन/2014 निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक  
19-05-2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा -  
प्रकरण क्रमांक 147/2011-12 अ-12 अपील

राम निरंजन पुत्र सुदर्शन प्रसाद

ग्राम कुइया तहसील हुजूर जिला रीवा

---आवेदक

विरुद्ध

रामरसीले मिश्रा पुत्र सुदर्शन प्रसाद

निवासी ग्राम कुइया तहसील हुजूर जिला रीवा

---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री महेश द्विवेदी)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री प्रमोद मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक // - ४ - 2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के प्रकरण  
क्रमांक 147/2011-12 अ-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-5-14  
के विरुद्ध म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत  
की गई है।

2/ प्रकरण का सारंश यह है कि अनावेदक ने नायब तहसीलदार वृत्त  
बनकुइया को आवेदन देकर बताया कि ग्राम कुइया स्थित भूमि सर्वे नंबर  
294/1 एवं 295/2 के अंश रकबा से 10 फुट चौड़ा रास्ता है जो नक्शा एवं  
खसरा में दर्ज कराया जाय। नायब तहसीलदार वृत्त बनकुइया ने प्रकरण क्रमांक  
2 अ-13/11-12 पंजीबद्ध किया तथा जांच कार्यवाही उपरांत पक्षकारों को


सुनकर आदेश दिनांक 28-6-12 पारित किया तथा अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। अनावेदक द्वारा इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 147/2011-12 अ-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-5-14 से नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-6-12 में हस्तक्षेप न करते हुये निर्देश जारी किये कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में स्थल निरीक्षक कर, मौके की स्थिति अनुसार साक्ष्य लेकर रुढ़ि एवं सुविधा के साथ जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं लेखी बहस के तथ्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने आदेश दिनांक 19-5-14 में विवेचित किया है कि नायब तहसीलदार ने आदेश पारित करते समय पुराने रास्ते के सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं की है। इसी प्रकार मौके की साक्ष्य लिये बिना तथा पटवारी प्रतिवेदन की समीक्षा किये बिना आदेश पारित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने वास्तविक स्थिति जानने के उद्देश्य से स्थल निरीक्षक कर, मौके की स्थिति अनुसार साक्ष्य लेकर रुढ़ि एवं सुविधा की जांच कर वास्तविकता पर अधारित प्रतिवेदन नायब तहसीलदार से माँगा है। इस संबंध में आवेदक के अभिभाषक की आपत्ति है कि अनुविभागीय अधिकारी को अपील स्वीकार करना चाहिये थी अथवा अस्वीकार। मामला प्रतिप्रेषित नहीं किया जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश दिनांक 19-5-14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने मामला नायब तहसीलदार को निराकृत करने के लिये प्रत्यावर्तित

नहीं किया है अपितु अपील का अंतिम निराकरण न करते हुये वास्तविकता पर आधारित जांच प्रतिवेदन मँगाया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 सँशोधन अधिनियम 2011 कमांक 42 के द्वारा धारा 49 की उपधारा (3) का प्रतिस्थापन किया गया है जिसके अनुसार प्रावधान है कि अपील न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या आवश्यक होने पर अतिरिक्त साक्ष्य लेगा। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अतिरिक्त साक्ष्य के उद्देश्य से एवं स्थल जाँच के उद्देश्य वावत् नायव तहसीलदार को निर्देश दिये हैं अपितु नायव तहसीलदार को मामला विनिश्चित करने हेतु प्रत्यावर्तित नहीं किया है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी हुजूर द्वारा जारी निर्देश दिनांक 19-5-14 में त्रुटि नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एवं अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 147/2011-12 अ-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-5-14 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

  
(एस0एस0अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर